अस्थिर शिक्षा नीति

लेखक – शैलजा मेनन (फैकल्टी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र- II (शासन व्यवस्था, शिक्षा) से संबंधित है।

द हिन्दू

15 जून, 2019

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा एक संस्थापक साक्षरता कार्यक्रम के लक्ष्यों के बारे में पुराने विचारों की पुष्टि करता है।"

भारत भर के प्रारंभिक कक्षाओं में कई बच्चे ठीक प्रकार से न तो पढ़ सकते है और न ही लिख सकते है, जैसा कि शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह स्कूल-आधारित सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और साथ ही समाज और अर्थव्यवस्थाओं के संचालन को भी प्रभावित करता है।

छोटे बच्चों की क्षमता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे में 'संस्थापक साक्षरता और न्यूमेरिसिटी' के लिए समर्पित एक अध्याय को देखकर बहुत खुशी हुई है। यह प्रारंभिक वर्षों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो स्वागत योग्य है और पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक वर्षों के बीच की सिफारिश की निरंतरता आवश्यक है। इसी तरह, मातृभाषा आधारित शिक्षा और मौखिक भाषा के विकास पर इसका जोर महत्त्वपूर्ण है।

हालांकि, एक विश्लेषण कि आखिर बच्चे क्यों बड़े पैमाने पर पढ़ने और लिखने में असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के आसपास के कारकों की ओर इशारा करते हैं जैसे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात आदि। जबकि इनमें से प्रत्येक कारक जो निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है, वे पर्याप्त स्पष्टता के साथ शैक्षणिक और शिक्षक शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं करते है, जो कई भारतीय कक्षाओं में प्रारंभिक साक्षरता के शिक्षण और सीखने को कमजोर बनाते हैं।

भारत भर के अधिकांश क्लासरूम में संस्थागत साक्षरता के काम को बच्चों को स्क्रिप्ट पढ़ाने और सरल शब्दों और वाक्य की समझ बढ़ाने में सक्षम बनाने के रूप में देखा जाता है। उच्च स्तर का अर्थ है महत्त्वपूर्ण चिंतन, पढ़ना और साहित्य पर प्रतिक्रिया देने से संबंधित है और लिखने की बात आमतौर पर स्कूली शिक्षा के बाद के वर्षों के लिए आरक्षित होते हैं। यह मसौदा एक नींव वाले साक्षरता कार्यक्रम के लक्ष्यों के बारे में इस तरह के प्रतिबंधात्मक और पुराने विचारों की पुष्टि करता है।

दुनिया भर के शोध प्रमाण इस बात को असमान रूप से प्रदर्शित करते हैं कि बहुत छोटे बच्चे स्वयं को अभिव्यक्त करने और संवाद करने के लिए शुरुआती रूप में पढ़ने, लिखने और ड्राइंग का उपयोग करने में सक्षम हैं। वे अर्थ-निर्माण, आलोचनात्मक सोच में भी सक्षम हैं। ड्राफ्ट में 'उभरती हुई साक्षरता' के रूप में संदर्भित छात्रवृत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया है।

अब इसका असर उन सिफारिशों पर होगा जिसका जिक्र ड्राफ्ट पालिसी में किया गया है जैसे बड़े पैमाने पर पूर्व-प्राथमिक ग्रेड के लिए मौखिक गतिविधियों का प्रस्ताव, ग्रेड 1-3 के लिए पढने के समय का निर्धारण और ग्रेड 4-5 के लिए लिखने के संदर्भ में अतिरिक्त घंटे को देना। यह सबूतों का खंडन करता है जिसका मानना है कि छोटे बच्चों को एक साथ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाना बेहतर है न कि क्रमिक रूप से ऐसा करना।

कई शैक्षणिक दृष्टिकोण

एक और चिंता की बात यह है कि सिफारिशें प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे कि कई आयु वर्ग लचीलेपन, खेल और गतिविधि-आधारित तरीकों से एक साथ सीखते हैं। वे प्रारंभिक साक्षरता के शिक्षण और सीखने के लिए विशिष्ट विचारों पर आकर्षित नहीं होते हैं। प्रारंभिक साक्षरता के लिए बच्चों को स्क्रिप्ट प्राप्त करने में मदद करने और उच्च क्रम का अर्थ बनाने के साथ उन्हें संलग्न करने के बीच एक 'संतुलन' की आवश्यकता होती है।

इसके लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक दृष्टिकोणों का ज्ञान भी आवश्यक है, जैसे कि बच्चों का जोर से पढ़ना, बच्चों को पढ़ने और लिखने के प्रयासों में उनका मार्गदर्शन करना, स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, उन्हें विभिन्न शैलियों के ग्रंथों के बारे में जानने में मदद करना आदि। इसके अलावा, इसमें सामग्री के संतुलन की आवश्यकता है जैसे पाठ्यपुस्तकों और कार्यपुस्तिकाओं से आगे बढ़कर

उच्च गुणवत्ता वाले बच्चों के साहित्य, स्वयं बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री आदि।

शिक्षकों को यह जानने की जरूरत है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों के लिए निर्देश को कैसे अलग किया जाए और संघर्षरत छात्रों को विशिष्ट मदद कैसे प्रदान की जाए। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की सिफारिशों के अनुसार पर्याप्त समय – प्रति दिन औसतन दो-तीन घंटे की आवश्यकता होती है।

हालांकि यह विशिष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए एक नीति दस्तावेज के दायरे से परे हो सकता है, इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे के लिए पर्याप्त दिशा प्रदान करनी चाहिए और इस मामले में, इसके कार्यान्वयन के लिए संस्थापक साक्षरता और जानकार शिक्षकों के लिए एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता का संकेत देना चाहिए। इस मुद्दे को संबोधित करने वाले पहले दस्तावेज (उदाहरण के लिए, एमएचआरडी के पढ़े भारत, बढ़े भारत, 2014 और अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रारंभिक भाषा और भारत में साक्षरता, 2016 के पेपर) विस्तारित समय और लक्ष्यों, विधियों और सामग्रियों के संतुलन के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण की सिफारिश करने में कहीं अधिक विशिष्ट रहा है।

शिक्षण की साक्षरता

यह मुद्दा एक और तीसरी चिंता है। यहाँ एक सवाल यह है कि इस बहुभाषी देश में संस्थापक साक्षरता को मूलभूत साक्षरता को सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे है और हैरानी की बात यह है कि इस बारे में चर्चा का अभाव है। दस्तावेज प्राथमिक ग्रेड में प्रारंभिक साक्षरता के अधिग्रहण का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवकों और समुदाय के सदस्यों की भर्ती करने की सिफारिश करता है, हालांकि, यह शिक्षकों के मार्गदर्शन में होता है।

यह एक खतरनाक और गलत विचार पर विश्वास करता है, जो कि कोई भी साक्षर व्यक्ति पढ़ा सकता है और बच्चों के विकास और सीखने से संबंधित परिष्कृत समझ को रेखांकित कर सकता है। स्वयंसेवकों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह एक प्राथमिक तंत्र नहीं हो सकता जिस पर राष्ट्रीय नीति छात्रों को मूलभूत साक्षरता प्रदान करने पर निर्भर करती है।

एक ओर आंगनवाड़ी के अनुभवों की गैर-शैक्षणिक प्रकृति की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरी ओर कई निजी प्री-स्कूलों द्वारा अनुचित पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ का अभ्यास करना, यह दर्शाता है कि इस मसौदे का निर्माण शुरुआती साक्षरता के क्षेत्र में विद्वानों, चिकित्सकों और नीति-निर्माताओं द्वारा किये गये प्रयासों के साथ संलग्न नहीं हैं।

GS World टीम...

नई शिक्षा नीति का मसौदा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी किये गये नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर उठे विवाद के बीच मसौदा नीति का संशोधित प्रारूप जारी किया गया, जिसमें गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- तमिलनाडु में द्रमुक और अन्य दलों ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि यह हिन्दी भाषा थोपने जैसा है।
- नई शिक्षा नीति बनाने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति में कुल 11 सदस्य हैं।

क्या हुआ संशोधन?

- संशोधित मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले के तहत छात्र अब कोई भी तीन भाषा पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि इनमें एक साहित्यिक भाषा जरूरी होगी।
- पुराने मसौदे में हिंदी, अंग्रेजी के साथ कोई एक स्थानीय भाषा पढ़ने का प्रावधान था।
- संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लचीला कर दिया गया है। अब इनमें किसी भी भाषा का जिक्र नहीं है।
- हालांकि संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में यह साफ कहा गया है कि स्कूली छात्रों को तीन भाषाये पढ़नी होंगी।

प्रमुख सिफारिशें

- इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।
- इस मसौदा नीति में लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों

के हटाने के विकल्प के साथ-साथ एम. फिल. प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

- इस मसौदा नीति के अनुसार, पी.एच.डी. करने के लिये या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया है।
- नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4 डिजाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है।
- यह मसौदा नीति धारा-12 (1) (सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है।

अन्य प्रमुख सिफारिशें

- स्कूली शिक्षा के लिये एक स्वतंत्र नियामक 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' (SSRA) और उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
- निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं, लेकिन वे मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में वृद्धि नहीं करेंगे। 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' द्वारा प्रत्येक तीन साल की अवधि के लिये इसका निर्धारण किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए शीर्ष निकाय 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की स्थापना की जाएगी, जो सतत् आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिये गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिये प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।
- विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

क्या है कस्तूरीरंगन समिति?

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने नई शिक्षा नीति (NEP) के लिए कस्तूरीरंगन कमेटी का जून 2017 में गठन किया था।
- इस समिति में 11 सदस्य थे। इससे पहले सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर साल 2015 में टी एस आर सुब्रमण्यन समिति का गठन किया था, लेकिन सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना।
- कस्तूरीरंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं।

शिक्षा के लिए चलाई गई योजनाएँ

- प्रारंभिक शिक्षा के लिए - सर्व शिक्षा अभियान-2001, समग्र शिक्षा, मिड डे मील योजना-1995
- पढ़े भारत, बढ़े भारत - 2014
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजनाएँ - 2009
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) 2013

Committed To

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. नई शिक्षा नीति का गठन के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है।
2. हाल ही में संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में स्कूली छात्रों को तीन भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी होगी।
3. नई शिक्षा नीति के इस मसौदे में पी.एच.डी. करने के लिए मास्टर डिग्री या तीन साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q. Consider the following statements-

1. New Education Policy has been prepared under the chairmanship of Kasturirangan.
2. Under the recent draft of amended education policy school students have to study three languages.
3. In the draft of new education policy, Master degree or three year graduation degree is necessary for P.H.D.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 में मसौदे में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए किन-किन बिन्दुओं पर बल दिया गया है? समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Which points have been emphasised to refom the education system in the recently released draft of National Education policy, 2019? Examine.

(250 Words)

नोट : 14 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed